to the retired officers of Public Sector Undertakings at par with the retired officers of the Central Government from the dates admissible to the latter.

## REPORTS OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Sir, I present the Hundred and Twenty Seventh and Hundred and Twenty Eighth Reports (in English and Hindi) of the Committee on Subordinate Legislation.

## REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Standing Committee on Agriculture:

- (i) First Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in Eighteenth Report of the Standing Committee on Agriculture (Twelfth Lok Şabha) on Demands for Grants (1999-2000) relating to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation).
- (ii) Second Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in Nineteenth Report of the Standing Committee on Agriculture (Twelfin Lok Sabha) on Demands for Grants (1999-2000) relating to the Ministry of Agriculture (Department of Agricultural Research and Education).
- (iii). Third Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in Twentieth Report (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1999-2000) relating to the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying).
- (iv). Fourth Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in Twenty-field

## [14 March, 2000] RAJYA SABHA

Report of the Standing Committee of Agriculture (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1999-2000) relating to the Ministry of Water Resources.

(v) Fifth Report on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in Twenty-second Report of the Standing Committee of Agriculture (Twelfth Lok Sabha) on Demands for Grants (1999-2000) relating to the Ministry of Food Processing Industries.

## Re. KILLING OF DALITS IN KARNATAKA

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश)। सभापति जी, आप मुझे एक मिनट की इजाजत दे दीजिए।

श्री सभापति : किस बात के लिए?

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, अभी 11 तारीख की रात को कर्नाटक के कोलार जिले के एक गांव में 200 आदिमयों ने अमानवीय ढंग से 7 दिलतों को जिंदा जलाया है। यह बड़ी दुखद घटना है । ऐसी घटनाएं सैकड़ों वर्षों से हो रही हैं, आजादी के बाद हो रही हैं। इस पर ह्यूमन राइट्स किमशन ने भी चिन्ता व्यक्त की है। अमरीका में बैठे हुए चिंता व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार का, खास तौर से हमारे गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अमानवीय कृत्य दिलतों के प्रति कोई नया प्रकरण नहीं है। हम बराबर इस संबंध में सदनों में चर्चा करते रहे हैं।

श्री सभापति : देखिए, मैंने कालिंग अटेंशन के लिए कहा है । मैंने आपको कहा था कि स्पेशल मेंशन दूंगा ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं एक वाक्य कहकर समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, आप भले ही बजट में सख्त कदम उठाएं, न उठाएं लेकिन इन मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए, सामूहिक जुर्माने करने चाहिए, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होनी चाहिए और वहां के जन प्रतिनिधि और जो अधिकारी हों उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए।

श्री सभापति : हो गया ।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश)ः : यह बहुत गंभीर मसला है...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, what is unfortunate is that, instead of arresting the accused, the Dalits are